सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 107 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 23 मई, 2026
मूल्य ₹ 3/-

जो अच्छा सेवक नहीं है वो अच्छामालिक नहीं बन सकता।

- प्लेटो

पंजाब का करो या मरो का मुकाबला लखनऊ... 7 | शहर की सरकार को पड़ी अदालत... 3 | भाजपा के कुराज में बिजली के... 2

सरकार ने आम जनता को दी महंगाई की एक और चोट

साइलेंट अटैक : 10 दिन में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम

» जनता को उबालो मत धीरे धीरे पकाओ वाली नीति पर अमल

» कांग्रेस का एक्स पर बयान मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने बढ़ोत्तरी का एलान किया है। इस बार सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है। पिछले 10 दिनों से ईंधन की कीमतों को तीन पर बढ़ाया जा चुका है जिससे लगभग में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।

सरकार जानती है कि अगर एक झटके में 10 रुपए बढ़ा दिए तो देशभर में हंगामा मच जाएगा। इसलिए जनता को उबालो मत, धीरे धीरे पकाओ वाली नीति अपनाई जा रही है। सुबह तेल कंपनियां नया झटका दे देती है और शाम तक टीवी चैनलों पर दूसरे मुद्दों का शोर शुरू हो जाता है। जनता अगली सुबह फिर लाइन में खड़ी होकर वही महंगा पेट्रोल भरवाती है और सत्ता को भरोसा हो जाता है कि देश अब विरोध नहीं करता सिर्फ सहन करता है।

महंगाई की असली चेन रिएक्शन

सरकार और तेल कंपनियां अक्सर पेट्रोल-डीजल के दामों को एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया बताती हैं। लेकिन सच यह है कि ईंधन की कीमत सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ाती बल्कि पूरे बाजार की रीढ़ हिला देती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी। ट्रक का किराया बढ़ेगा तो सीमेंट और सरिया महंगे होंगे। डीजल बढ़ेगा तो खेती की लागत बढ़ेगी। यानी पेट्रोल पंप पर लगी आग सीधे रसोई तक पहुंचती है। यही वजह है कि आम आदमी को सिर्फ तेल नहीं पूरी जिंदगी महंगी महसूस होने लगती है।

> ईंधन की कीमत सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ाती बल्कि पूरे बाजार की रीढ़ हिला देती है।

लेकिन सरकार की तरफ से हर बार वही पुराना तर्क दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं तब जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? देश की विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि सरकार तेल कंपनियों के हितों की ज्यादा चिंता करती है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि दुनिया भर की सरकारें जनता को राहत देने में लगी हैं जबकि भारत में जनता से ही वसूली की जा रही है। यह आरोप राजनीतिक जरूर है लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवालों से मेल खाता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर टैक्स कम किए जाएं तो क्या सच में देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी? या फिर सरकार को डर है कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया कमजोर पड़ जाएगा? पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स आज सरकारों की सबसे मोटी कमाई में शामिल हैं। यही कारण है कि हर सरकार विपक्ष में रहते हुए कीमतों पर हंगामा करती है और सत्ता में आते ही चुप हो जाती है।

सबसे ज्यादा पिस रहा है मध्यम वर्ग

गरीब को योजनाओं का सहारा मिल जाता है अमीर पर महंगाई का असर कम पड़ता है। लेकिन मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा दबाव झेलता है।

उसकी सैलरी तय है खर्च अनियंत्रित है। ऑफिस जाने वाला कर्मचारी अब महीने का बजट पेट्रोल के हिसाब से बनाता है। छोटी दुकानों का मुनाफा ट्रांसपोर्ट लागत खा जाती है। यानी यह सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं देश के आर्थिक संतुलन का सवाल बन चुका है। अगर ईंधन लगातार महंगा होता रहेगा तो

आने वाले समय में जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से और दूर होती जाएगी। यह सवाल अब सिर्फ विपक्ष नहीं देश की जनता भी पूछ रही है। क्या सरकार टैक्स कम करेगी? क्या तेल कंपनियों पर नियंत्रण होगा? क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? या फिर धीरे-धीरे वाला यह खेल आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि सच यही है कि जनता सब समझ रही है। धीरे-धीरे बढ़ती कीमतें अब धीरे-धीरे गुस्से में बदल रही हैं।

फिर पंपो पर बढ़ी भीड़

देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही है, फ्यूल स्टेशनों में लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए जमा हो रहे हैं, बढ़ती भीड़ को देखकर लोगों में घबराहट और बढ़ रही है।

धीरे-धीरे वाली राजनीति का मनोविज्ञान

राजनीति में अब सिर्फ फैसले नहीं उनकी टाइमिंग और प्रस्तुति भी मायने रखती है। जनता को एक साथ बड़ा झटका देने के बजाय छोटे-छोटे झटकों में दर्द बांट दिया जाता है। इससे विरोध कमजोर पड़ता है। सोशल मीडिया पर दो दिन ट्रेंड चलता है फिर नया मुद्दा आ जाता है। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें अब सिर्फ आर्थिक नहीं मनोवैज्ञानिक खेल भी बन चुकी हैं। सरकार को पता है कि जनता अचानक हुए विस्फोट पर ज्यादा प्रतिक्रिया देती है लेकिन धीरे-धीरे बढ़ती परेशानी को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करने लगती है।

इंडियन ऑयल ने दाम बढ़ने पर दी अजीब सफाई

दाम बढ़ने पर अब इंडियन ऑयल ने अपनी सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, जो दिक्कतें कुछ जगहों पर दिख रही हैं वह अस्थायी समय के लिए है, इंडियन ऑयल के मुताबिक, इस वक्त कटाई का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से डीजल की मांग बढ़ी है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट पेट्रोल पंपों पर दाम ज्यादा होने से वहां के ग्राहक सरकारी पंपों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बड़े संस्थागत खरीदार भी इन दिनों पीएसयू पंपों से ईंधन ले रहे हैं क्योंकि बल्क सप्लाई के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से काफी ऊंचे हैं। इन सब वजहों से कुछ खास इलाकों में मांग एकाएक बढ़ी है।

किसान खेत कम और चिंता ज्यादा जोत रहा है

क्या देश में सड़कें मुफ्त हो गई? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हो गया? क्या किसानों का डीजल सस्ता हुआ? क्या ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हुआ? नहीं! उल्टा हर चीज महंगी होती चली जा रही है। दूध से लेकर सब्जी तक, बस किराए से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक हर चीज के पीछे पेट्रोल-डीजल की आग लगी हुई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिये इस महंगाई पर तंज कसा है कि महंगाई मैन पीएम मोदी ने 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए। सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है सवाल उस मध्यमवर्ग का है जो हर महीने सैलरी आने से पहले ही ईएमआई और पेट्रोल के बीच पिस जाता है। सवाल उस गरीब का है जो अब बाइक निकालने से पहले किलोमीटर नहीं जेब में पड़े नोट गिनता है। सवाल उस किसान का है जिसका ट्रैक्टर अब खेत कम और चिंता ज्यादा जोतता है।

भाजपा के कुराज में बिजली के केवल दाम बढ़ रहे हैं: अखिलेश यादव

सपा प्रमुख बोले- नये प्लांट लगाना तो इस सरकार के बस में नहीं था

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में बिजली संकट के लिए भाजपा की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स अकाउंट से लिखा- बिजली के नये प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुंह से ये कह ही देते '3× 660 सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट, तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती। भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ 'माग' बढ़ रही है या 'दाम' बढ़ रहे हैं, सप्लाई-आपूर्ति नहीं। भाजपा राज, यूपी खस्ताहाल।

वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार के दो कार्यकाल बिना किसी उपलब्धि के समाप्ति की ओर है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया है। किसानों की फसलों की लूट मची है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा राज में महिलाएं उपेक्षित और अपमानित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है। इस सरकार ने प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा कर दी है। लगभग हजारों स्कूल बंद कर दिए। हजारों स्कूलों में एडमिशन शून्य है। अस्पतालों में मरीजों को दवा-इलाज नहीं मिल रहा है। मरीज मारे-मारे फिर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण व्यापक है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। सबको साथ लेकर चलती है। लोकतंत्र को मजबूती देती है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के साथ है। भाजपा सामाजिक न्याय विरोधी है। भाजपा आरक्षण की लूट कर रही है। पीडीए का हक खा रही है। पीडीए समाज की संख्या और जनाधार की तुलना में भाजपा की स्थिति शून्य है।

अदृश्य शस्त्र देश, समाज और आपसी प्रेम पर अंदर से हमला कर रहे हैं

वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में बाहुबली नेताओं, आपराधिक छवि के लोगों के आर्म्स लाइसेंस पर सभी जिलों से मांगी गयी रिपोर्ट के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, असली शस्त्र के तो लाइसेंस बनते हैं लेकिन कुछ अदृश्य शस्त्र भी हैं, जो गुप्त रूप से देश, समाज और आपसी प्रेम पर अंदर से बेहद घातक हमला कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने इसको लेकर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया है। उन्होंने बीजेपी पर अवैध रूप से दुकान, कार्यालय के नक्शे बनाने का भी आरोप लगाया और इनकी वैद्यता की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके बीजेपी नेताओं और उनके करीबियों पर सीधे आरोप लगाते हुए लिखा कि इसके अतिरिक्त जनता की जिज्ञासा ये भी है कि गुप्त-गतिविधियों में संलिप्त भाजपाई संगी-साथियों के ऐसे निर्माणों को 'कार्यालय' कहा जाए या 'अड्डा'? इन 'संगी-साथी' अवैध लोगों का ख़र्चा-पानी कौन उठाता है? इसका कच्चा चिट्ठा तलाशकर खोला जाए। ये तथाकथित स्वदेशी 'संगी-साथी', विदेश भ्रमण करने क्यों जाते हैं?

भाजपा चालाक और अहंकारी पार्टी

श्री यादव ने कहा कि भाजपा चालाक और अहंकारी पार्टी है। इसने लोकतंत्र को धोखा दिया है। भाजपा राजनीतिक दल नहीं गैंग है। भाजपाई गरीबों और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे है। भाजपा ने भूमाफिया बनाये हैं। उन्हें संरक्षण देती है। 27 विधानसभा का चुनाव यूपी की जनता के भविष्य का चुनाव है। चुनाव में भाजपा को दो दशक का हिसाब देना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत भाजपा का सफाया कर देगी।

बसपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा

बसपा अध्यक्ष मायावती की सेहत को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर आक्रोश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती की सेहत को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से बसपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर बसपा कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं को खरी-खरी सुनाने में पीछे नहीं हट रहे तो पार्टी पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बता दें कि मायावती खुद कई बार अपनी सेहत ठीक होने का दावा करती रही हैं, इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने यह शिगूफा छोड़कर सियासी तनातनी बढ़ा दी है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक कांग्रेस की मायावती की सेहत को लेकर की गई टिप्पणी सोची-समझी साजिश के तहत की गई है ताकि बसपा पर गठबंधन करने का दबाव बनाया जा सके। इसी वजह से दलित नेताओं को मायावती से मिलने भेजा गया था। कांग्रेस का यह दांव भी उल्टा पड़ गया क्योंकि बसपा कैडर में इसे लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

बीते दिनों मायावती के दिल्ली प्रवास के दौरान भी कांग्रेस ने कुछ शिगूफे छोड़े थे ताकि बसपा को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सके। फिलहाल मायावती ने कांग्रेस के इस कदम और भ्रामक बयानबाजी को लेकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। आगामी 24 मई को पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में मायावती इस बाबत कार्यकर्ताओं को संदेश दे सकती हैं।

बिजली संकट पर सरकार लोगों की चिंता समझे : मायावती

लखनऊ। बिजली संकट पर बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स अकाउंट से लिखा- सरकार लोगों की चिंता को समझे। बसपा प्रमुख ने लिखा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम अपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है तथा इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में भी काफी व निरन्तर रहती है। अत: सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति सम्बंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुये जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे। इसके साथ ही, नये पावर प्लाण्ट आदि के माध्यम से भी आगे के लिये बिजली आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे तो यह व्यापक जनहित में उचित होगा।

गाय को राजनीतिक नफा-नुकसान का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए: नीरज

जेडीयू नेता बोले-बकरीद के मौके पर कुर्बानी दी जाती है तो मां कामाख्या के दरबार में भी बलि चढ़ाने की सनातन परंपरा है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को अगले सप्ताह मनाए जाने वाले ईद उल अजहा के मद्देनजर मांगी गई छूट के संबंध में पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हाल ही में एक निजी मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि आज के बदलते दौर में गाय को राजनीतिक नफा-नुकसान का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए या नहीं, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि गाय हमेशा से सभी के लिए गहरे आदर और सम्मान का प्रतीक रही है।

त्योहारों और धार्मिक परंपराओं पर अपनी राय रखते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि यदि बकरीद के मौके पर कुर्बानी दी जाती है, तो दूसरी तरफ मां कामाख्या के पावन दरबार में भी बलि चढ़ाने की सनातन परंपरा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई इस मामले में राजनीतिक बलि की बात कर रहा है, तो वह विषय बिल्कुल अलग है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

रास्ते पर नमाज पर रोक के खिलाफ कोर्ट जाएगी तृणमूल

ममता बनर्जी ने पार्षद को दिया निर्देश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर राज्य सरकार की पाबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है।

पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने मेटियाबुरुज की एक तृणमूल पार्षद को इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि संबंधित पार्षद जल्द ही इस मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। कालीघाट स्थित आवास पर ममता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम के तृणमूल पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी प्रतिबंध का मुद्दा उठा। सूत्रों का दावा है कि चर्चा के दौरान ममता ने संबंधित पार्षद को तत्काल अदालत जाने के लिए कहा। दूसरी ओर राज्य सरकार की सख्ती के बाद शुक्रवार को कोलकाता के राजाबाजार, तपसिया, पार्क सर्कस और तिलजला जैसे इलाकों में सड़क रोककर नमाज नहीं पढ़ी गई। मस्जिदों के भीतर ही दो चरणों में जुम्मे की नमाज की व्यवस्था की गई, जिसके चलते मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यहां कालीघाट स्थित अपने आवास पर कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के पार्षदों के साथ बैठक की।

शहर की सरकार को पड़ी अदालत की फटकार

मेयर की हठ से बन गया राजधानी में नया इतिहास

- पार्षद को शपथ न दिलाना लखनऊ मेयर पर पड़ा भारी
- हाईकोर्ट ने वित्तीय-प्रशासनिक अधिकार किए गए फ्रीज
- मेयर अस्पताल में भर्ती
- समाजवादी पार्टी के ललित किशोर ने डाली थी याचिका
- विकास कार्यों का काम बहाली न होने तक डीएम के जिम्मे

मो.शारिक/4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ में शहर की सरकार को कोर्ट की फटकार लगी है। इस फटकार के साथ ही नया इतिहास भी बन गया है। दरअसल लखनऊ हाई कोर्ट ने एक पार्षद के शपथ ग्रहण के मामले में उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। इस फैसले के बाद से शहर का सियासी पारा भी उबाल मार रहा है।

एकबार फिर विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी शहर की प्रथम नागरिक की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। अब आगे देखना हो कि क्या होगा। पर कोर्ट के इस आदेश से राजधानी के विकास पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। हालांकि वहीं इस आदेश के आने से पहले मेयर अस्पताल में भर्ती हो गईं थी। यहां ये बता दें कि एक पार्षद को शपथ न दिलवाने के कारण कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा। मेयर सुषमा खर्कवाल की परेशानी बढ़ गई है। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने एक पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाने के मामले में कोर्ट का आदेश न मानने पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। लखनऊ के डीएम और नगर आयुक्त को मेयर के स्थान पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

जब तक पार्षद को शपथ नहीं दिलाया जाता है, तब तक मेयर के अधिकार बहाल नहीं होंगे

कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जब तक पार्षद को शपथ नहीं दिलाया जाता है, तब तक मेयर के अधिकार बहाल नहीं होंगे। हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 में को होगी। वहीं, कोर्ट का आदेश आने के बाद मेयर सुषमा खर्कवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने 19 मई से बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की बात कही। मेयर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में किया जाएगा।

सुषमा खर्कवाल नगर निगम चुनाव 23 में जीत दर्ज कर बनीं मेयर

सुषमा खर्कवाल भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में बड़ी महिला नेता के रूप में जानी जाती है। लखनऊ नगर निगम चुनाव 23 में जीत दर्ज कर वह शहर की पांचवीं मेयर बनीं। उन्होंने 26 मई 23 को मेयर पद की शपथ ली थी। सुषमा खर्कवाल मूल रूप से उत्तराखंड की हैं। उनके पति प्रेम खर्कवाल भारतीय सेना से रिटायर्ड हवलदार हैं। वे 30 सालों से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। अवध क्षेत्र महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया है। सुषमा खर्कवाल सैनिक कल्याण बोर्ड और रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की सदस्य भी रह चुकी है। लखनऊ में दो लाख बांग्लादेशी के प्रवेश करने वाला बयान देकर वे खूब चर्चा में आई थीं। साथ ही, अगस्त 24 में उन्होंने नालों की सफाई न होने पर निगम अधिकारियों को नालों में फेंकने की धमकी देकर चर्चा में आई थीं।

जो आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा : मेयर

मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि कोर्ट का आर्डर नहीं मिला है मगर जो आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा। अभी अस्पताल में हूं। दो-तीन में वहां से आने के बाद आदेश देखकर आगे की कार्यवाही करूंगी।

संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को कोर्ट के आदेश को मनाना चाहिए : मुकेश सिंह

कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को कोर्ट के आदेश को मनाना चाहिए। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही संविधान को नहीं मानता तो उनके नेता उसी पथ पर चलकर उच्च न्यायालय के आदेश को नजरंदाज करना उन्हें भारी पड़ गया। उच्च न्यायालय ने मेयर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो पर रोक लगाना यह साबित करता है कि न्यायालय से कोई बड़ा नहीं

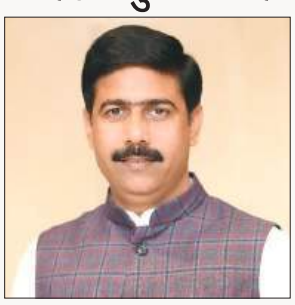

हो सकता है। न्यायालय से निर्वाचित किये गये पार्षद को शपथ दिलाने के लिए मेयर बाध्य है।

खर्कवाल ने बना दी नई इबारत

लखनऊ मेयर सुषमा खर्कवाल ऐसी पहली मेयर बन गई है, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट ने प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को सीज करने का आदेश दिया है। स्थानीय निकाय की राजनीतिक और न्यायिक इतिहास का यह पहला मामला बताया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के तहत मेयर के तमाम अधिकार सीज कर दिए गए हैं। सुषमा खर्कवाल अब हाई कोर्ट के आदेश के कारण नगर निगम प्रशासन से संबंधित कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगी। ऐसे में अब उनके सामने वार्ड पार्षद ललित किशोर तिवारी का शपथ ग्रहण करने का विकल्प बचा है। माना जा रहा है कि अब जल्द से जल्द मेयर इस पर निर्णय ले सकती हैं।

जिलाधिकारी देखेंगे काम

कोर्ट ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को अगले आदेश नगर निगम का काम देखने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश ललित किशोर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि अगली सुनवाई की तिथि 21 मई तक शपथ नहीं दिलाई गई तो लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और मेयर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी और नगर आयुक्त पेश हुए। अदालत ने निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ न दिलाए जाने पर अफसरों को फटकार लगाई। साथ ही पिछली सुनवाई के समय के आदेश का पालन न करने पर मेयर के अधिकार फ्रीज कर दिए।

सपा पार्षद ने किया था कोर्ट का रुख

लखनऊ नगर निगम के वार्ड 73 में नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के प्रदीप शुक्ला ने जीत दर्ज की थी। वहीं, समाजवादी पार्टी के ललित किशोर तिवारी दूसरे स्थान पर रहे थे। बाद में सपा प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी ने कोर्ट में प्रदीप शुक्ला के खिलाफ यशिका दायर की। इसमें उन पर नामांकन के चुनावी हलफनामे में दूसरी शादी और कुछ अनिवार्य एवं व्यक्तिगत जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। कोर्ट में

मामला चला। दोनों पक्षों की दलील में कोर्ट ने ललित किशोर तिवारी के पक्ष को सही मानते हुए प्रदीप शुक्ला के निर्वाचन को रद्द कर दिया। वहीं, ललित किशोर तिवारी को 19 दिसंबर 2025 को वार्ड 73 के पार्षद के तौर पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। हालांकि, पिछले 5 महीने से ललित किशोर तिवारी को शपथ नहीं दिलाई जा सकी है। मेयर की ओर से पार्षद के तौर पर शपथ ग्रहण न कराए जाने के मामले में ललित किशोर तिवारी हाई कोर्ट चले गए। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने 12 मई को इस संबंध में मेयर को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देने के साथ ही शपथ ग्रहण को अटकाए रखे जाने के संबंध में गंभीर सवाल किया था। मेयर को तत्काल ललित किशोर तिवारी का शपथ ग्रहण करने का आदेश दिया गया।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

इस तरह तो एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा देश

अंग्रेजों के जमाने में जो बड़े-बड़े छायादार पेड़ लगाए गए थे वे काटे जा रहें हैं पर उनके बदले पेड़ उतने नहीं लगाए जा रहे हैं। जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वह देखभाल न करने से मुरझा रहे हैं । विकास जरुरी है पर उससे हो रहे विनाश को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा नहीं तो पूरा देश एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा।

पिछले तीच चार दिनों से भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ऐसे समाचार आने लगे हैं भारत दुनिया का सबसे गर्म देश हो गया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इस हालात के लिए सरकार के साथ आमजन भी है। अंधाधुंध विकास के चलते हमने प्रकृति व पर्यावरण का दोहन किया आज भी करे जा रहे हैं। सरकारे अरावली, अंडमान से लेकर समुद्री इलाकों में विकास के नाम पर जंगलों को काट रही हैं जल स्रोतों को पाट रही हैं। आलम ये हैं अंग्रेजों के जमाने में जो बड़े-बड़े छायादार पेड़ लगाए गए थे वे काटे जा रहें हैं पर उनके बदले पेड़ उतने नहीं लगाए जा रहे हैं। जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वह देखभाल न करने से मुरझा रहे हैं। विकास जरुरी है पर उससे हो रहे विनाश को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा नहीं तो पूरा देश एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा। भीषण गर्मी से लडने की योजना बंद कमरों में बैठकर नहीं बन सकती। हमें जलवायु पर चर्चा करने से पहले उस जीवन शैली को समझना होगा, जो प्रकृति के साथ चलती थी।

हमारे घर कैसे बनते थे, हमारा भोजन क्या था और हमारे जल स्रोतों का प्रबंधन कैसे होता था-इन सभी बातों को समझना आवश्यक है। कुछ समय पहले की बात है। मैं दिल्ली के पास एक गांव में चाय के ठेले पर बैठा था। बात गर्मी की चल पड़ी। ठेले वाले ने कहा, 'गर्मी तो पहले भी होती थी, साहब, पर अब कठिन लगने लगी है।' फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। पहले बड़ी इमारतों में गिनती के एयर कंडीशनर हुआ करते थे। अब हर खिडक़ी से एक एसी बाहर की ओर गर्मी फेंकता है। हर मोहल्ले के चौराहे पर मटकों के ठिए हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जगह पानी की बोतलें बिकती हैं। पहले जब मेहमान घर आते थे, तो उन्हें कैरी का पना या छाछ पिलाई जाती थी, ताकि लू का असर कम हो। अब उनकी जगह दवाइयों ने ले ली है। आस-पास बैठे बुजुर्ग सिर हिलाकर सहमति जताते रहे और मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। आज मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़े देखकर ही हम असहज महसूस करने लगते हैं। हमारी जीवनशैली और प्रकृति को जीतने की हमारी कोशिशें ही गर्मी को बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर आदिवासी और ग्रामीण जीवन शैली है, जो प्रकृति से लडक़र नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर स्वयं को सुरक्षित रखती है। वही जीवन शैली हमें प्रकृति के साथ रहकर आनंद लेना भी सिखाती है। यह जीवन शैली पहले भी महत्त्वपूर्ण थी और आज भी उतनी ही आवश्यक है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

चुनावी तंत्र में भरोसा कायम रखने की चुनौती

दिनेश भारद्वाज

भारत में चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं होते, वे लोकतंत्र की सामूहिक वैधता का उत्सव भी होते हैं। लेकिन जब मतदाता सूची ही सवालों के घेरे में आ जाए, तब लोकतंत्र की पूरी संरचना बहस के केंद्र में आ खड़ी होती है। यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा चरण केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का संवेदनशील अध्याय बन गया है। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर लागू करने का कार्यक्रम घोषित किया है। इनमें ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, तथा चंडीगढ़ को शामिल किया गया है।

इनमें से कई राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को केवल 'मतदाता सूची सुधार अभियान' मानकर नहीं देखा जाएगा। इसके राजनीतिक अर्थ, चुनावी प्रभाव व लोकतांत्रिक संकेत दूरगामी होंगे। चुनाव आयोग का तर्क है कि इस मुहिम का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। मृत मतदाताओं के नाम हटाने हैं, डुप्लीकेट वोट समाप्त करने हैं, माइग्रेशन के कारण बदले पते अपडेट करने हैं और नए पात्र मतदाता जोड़ने हैं। लेकिन राजनीति केवल सिद्धांतों से नहीं; आशंकाओं व अनुभवों से भी संचालित होती है। ऐसे में एसआईआर तकनीकी प्रक्रिया कम और राजनीतिक बहस अधिक बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतदाता सूची को लेकर विवाद उठते रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगाते रहे कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं या फिर चुनावी लाभ के लिए वोटर लिस्ट में 'मैनेजमेंट' किया जा रहा है।

हाल में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद यह बहस और तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है, चुनावी प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं। दूसरी ओर केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक हार की हताशा बताते हैं। यानी मतदाता सूची अब केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रही; राजनीतिक विश्वास और अविश्वास की कसौटी बन चुकी है। यहीं बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने की निष्पक्ष

प्रक्रिया है,या फिर राजनीति के ध्रुवीकरण में यह भी नया सियासी औजार बनता जा रहा है? इस विशाल देश में लगातार माइग्रेशन, शहरीकरण और जनसंख्या गतिशीलता के कारण मतदाता सूची को अद्यतन रखना बेहद कठिन कार्य है। करोड़ों लोग रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कारणों से लगातार स्थान बदलते हैं। लाखों लोग मृत्यु के बाद भी वर्षों तक वोटर लिस्ट में बने रहते हैं। डुप्लीकेट वोट भी हैं। यदि निर्वाचन आयोग समय-समय पर व्यापक पुनरीक्षण न करे तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है, सत्यापन प्रक्रिया कई बार चयनात्मक दिखाई देती है। खासकर गरीब, प्रवासी, किरायेदार और हाशिये पर खड़े वर्गों के मतदाता सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन लोगों के पास स्थायी दस्तावेज नहीं, बार-बार पता बदलता है, या जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, वे सबसे पहले सूची से बाहर होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग दुनिया की सबसे विश्वसनीय चुनावी संस्थाओं में गिना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। ऐसे में एसआईआर उसके लिए भी बड़ी परीक्षा है। ऐसे में निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखना भी जरूरी होगा। यदि लाखों मतदाताओं के नाम कटते हैं तो आयोग को पारदर्शी तरीके से यह बताना होगा कि किन आधारों पर कार्रवाई हुई। लगभग सभी राजनीतिक दल सिद्धांतत: 'शुद्ध मतदाता सूची' के पक्ष में हैं, लेकिन व्यवहार में हर दल की चिंता अपने वोट बैंक को लेकर है। यदि किसी राज्य में बड़ी संख्या में शहरी प्रवासी मतदाता सूची से बाहर होते हैं तो इसका प्रभाव अलग होगा।

ग्रामीण इलाकों में नाम कटते हैं तो समीकरण अलग होंगे। यदि नए युवा मतदाता बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो चुनावी रुझान बदल सकते हैं। यानी एसआईआर चुनावी गणित का भी बड़ा कारक है। यही वजह है कि सभी दल बूथ स्तर तक अपने बीएलए सक्रिय कर रहे हैं ताकि उसका समर्थक वोटर सूची में बना रहे और विरोधी पक्ष की संभावित 'गड़बड़ियां' पकड़ी जाएं। देश में मतदाता सूची भी राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुकी है। बहस का मूल प्रश्न एसआईआर का होना या नहीं होना नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत की चुनावी प्रणाली आम नागरिक में भरोसा पैदा कर पा रही है? जब कोई मतदाता यह महसूस करने लगे कि उसका वोट सुरक्षित नहीं है या चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव है।

हंतावायरस इबोला से फिर स्वास्थ्य चुनौती

मुकुल व्यास

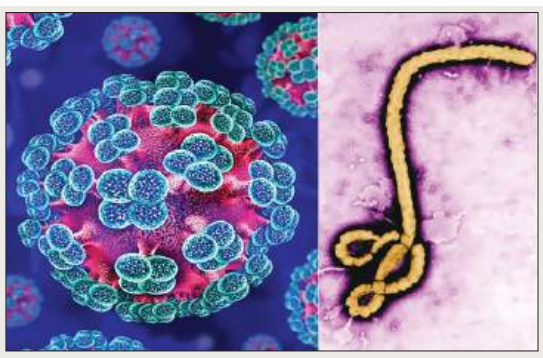

कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज, एमवी होंडियस पर हंतावायरस के मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। यह वायरस हफ्तों से दुनिया के एक ऐसे हिस्से में फैल रहा है, जहां गृह युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। साथ ही, इसमें शामिल इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है। इसलिए इस वायरस को रोकने के लिए अधिकारियों के पास कम ही साधन उपलब्ध हैं। यह वायरस संक्रमित लोगों में से लगभग एक-तिहाई लोगों की जान ले लेता है। यह इस महामारी के फैलने का एक बहुत ही नाजुक दौर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रतिनिधि ऐन एन्सिया ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप, जिसने कम से कम 131 लोगों की जान ले ली है, शायद मूल अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डॉ. एन्सिया ने बताया कि जांच से यह और भी साफ होता जा रहा है कि यह बीमारी दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी है। अभी तक डीआर कांगो में 513 से ज्यादा मामलों का संदेह है, जबकि पड़ोसी देश युगांडा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लंदन स्थित एमआरसी सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एनालिसिस द्वारा जारी किए गए एक मॉडल के अनुसार, इबोला के बहुत से मामले पकड़ में नहीं आए हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामलों की संख्या 1,000 से अधिक है। दरअसल, मौजूदा प्रकोप जितना अभी दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और इसका असली दायरा अभी भी अनिश्चित है। 6 अमेरिकी नागरिकों के वायरस के संपर्क में आने की सूचना मिली है। इबोला के अधिकतर मामले छोटे स्तर के ही होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ 2014-16 में फैली महामारी को याद करके नए प्रकोप पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उस समय पश्चिम अफ्रीका में इबोला के सबसे बड़े प्रकोप के दौरान 28,600 लोग संक्रमित हुए थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी' घोषित किया है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कोविड जैसी किसी बड़ी महामारी के शुरुआती दौर में पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया के लिए इबोला से होने वाला खतरा अब भी कम है। वर्ष 2014-16 में इबोला महामारी के दौरान भी ब्रिटेन में इबोला के केवल तीन मामले सामने आए थे, और वे सभी स्वास्थ्यकर्मी थे जो स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए थे। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के पैंडेमिक साइंसेज इंस्टिट्यूट की वैज्ञानिक डॉ. अमांडा रोजेक का कहना है कि नए प्रकोप पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी तालमेल की जरूरत है। युगांडा, दक्षिण सूडान और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह इबोला अब भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देशों को व्यापार और यात्रा के घनिष्ठ संबंधों के कारण 'उच्च जोखिम' वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इबोला एक गंभीर और जानलेवा संक्रामक बीमारी है।

दरअसल, इबोला वायरस स्वाभाविक रूप से जानवरों, मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन अगर लोग उनके सीधे संपर्क में आते हैं, तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। इस प्रकोप का कारण इबोला वायरस की बुंडिबुग्यो प्रजाति है। यह उन तीन प्रजातियों में से एक है, जिनके कारण संक्रमण फैलता है। बुंडिबुग्यो ने पहले केवल दो बार प्रकोप फैलाया है। वर्ष 2007 और 2012 में इसने संक्रमित लोगों में से लगभग 30 प्रतिशत की जान ले ली थी। बुंडिबुग्यो वायरस स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां खड़ी करता है। इबोला वायरस की अन्य प्रजातियों के विपरीत बुंडिबुग्यो के लिए कोई भी स्वीकृत टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ प्रायोगिक दवाएं अवश्य मौजूद हैं। वायरस के संक्रमण की पुष्टि करने वाले टेस्ट बहुत कारगर नहीं हैं। इस प्रकोप के शुरुआती नतीजे इबोला वायरस के लिए नेगेटिव आए थे और वायरस की पुष्टि करने के लिए अधिक उन्नत प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। इसमें बुंडिबुग्यो भी शामिल है। ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर टूडी लैंग कहती हैं कि बुंडिबुग्यो से निपटना इस प्रकोप में एक बहुत बड़ी चिंता है। समझा जाता है कि संक्रमण होने के दो से 21 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये फ्लू के लक्षणों जैसे होते हैं जिनमें बुखार, सिरदर्द और थकान शामिल हैं।

लेकिन जैसे-जैसे इबोला बढ़ता है, इससे उल्टी, दस्त और शरीर के अंगों का काम करना बंद हो जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कुछ मरीजों को शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव की समस्या भी हो जाती है। बुंडिबुग्यो वायरस को सीधे निशाना बनाने के लिए कोई भी स्वीकृत दवा उपलब्ध न होने के कारण इसका इलाज बेहतर सहायक देखभाल पर निर्भर करता है, जिसमें दर्द, अन्य संक्रमणों, शरीर में तरल पदार्थों और पोषण का प्रबंधन शामिल है। शुरुआती देखभाल से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। अफ्रीका में इबोला के मामले सामने आने से कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज पर कुछ यात्रियों के हंतावायरस के संक्रमित लोगों की खबर ने कोविड के दिनों की याद ताजा कर दी। छह साल पहले, मार्च 2020 में एक क्रूज जहाज रूबी प्रिंसेस के सिडनी में डॉक होने के बाद कोविड फैल गया था। जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 575 लोग कोविड से संक्रमित थे। इसके बाद यह वायरस और दूसरे लोगों में भी फैल गया।

आलू का रस

त्वचा के लिए है रामबाण

आज के समय में प्रदूषण, गलत खानपान और तनाव के कारण त्वचा की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स की ओर रुख करते हैं, लेकिन कई बार इनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप बिना किसी केमिकल के अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो किचन में मौजूद एक साधारण चीज आपकी बड़ी मदद कर सकती है। आलू का रस त्वचा की देखभाल के लिए बेहद असरदार घरेलू नुस्खा माना जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की रंगत निखारने में मदद करते हैं। नियमित रूप से आलू के रस का सही तरीके से इस्तेमाल करने से कई दिक्कतों से राहत मिल सकती है।

इस्तेमाल का तरीका

रस निकालने के बाद एक कॉटन पैड या रुई लें और उसमें आलू का रस डुबोकर चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं। रस लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक त्वचा पर लगा रहने दें ताकि इसके पोषक तत्व स्किन में अच्छे से समा सकें। समय पूरा होने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें और हल्का मॉइश्चराइज़र लगा लें। बेहतर और जल्दी असर के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार इस उपाय को अपनाया जा सकता है।

ऐसे निकालें रस

आलू का रस इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक ताजा और कच्चा आलू लें। उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी या गंदगी पूरी तरह हट जाए। अब आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें या मिक्सर में पीस लें। इसके बाद एक साफ सूती कपड़े या छलनी की मदद से उसका रस निकाल लें। इसका प्रयोग स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ से भरपूर आलू के रस में चावल का आटा मिलाकर चेहरे पर लगाने से टैनिंग की समस्या हल होने लगती है। 10 से 15 मिनट तक उसे चेहरे पर लगाए रखने के बाद धो दें। इसके अलावा आलू के स्लाइज़ को चेहरे पर रगड़ने से भी अनइवन टोन से राहत मिल जाती है। इसके अलावा चेहरे पर दाग धब्बों की समस्या को दूर करने और नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए आलू के रस में शहद की बूंदों और चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे पर कॉटन की मदद से लगाएं। हल्दी में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण दाग धब्बों के अलावा स्किन इंफ्लामेशन को भी कम करता है। वहीं आलू के रस में विटामिन ई कैप्सूल और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर एक फेसपैक तैयार कर लें। अब उसे चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। पैक सूखने के बाद गुलाब जल की कुछ बूंदों को हाथों पर लेकर चेहरे की मसाज करें और सामान्य पानी या गीले तौलिए से चेहरे को क्लीन कर लें।

रस के फायदे

आलू का रस त्वचा के लिए एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, जिससे चेहरे की रंगत धीरे-धीरे निखरने लगती है और नेचुरल ग्लो आता है। इसमें मौजूद एंजाइम्स और विटामिन C त्वचा की डलनेस को कम करने में मदद करते हैं। यह सन टैनिंग और धूप से होने वाले सनबर्न की समस्या को शांत करता है और त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। आलू के रस में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों और पिंपल्स की लालिमा को कम करने में सहायक होते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन और झाइयों की समस्या धीरे-धीरे हल्की पड़ सकती है।

हंसना मना है

सरदार लड़की वालों के यहां रिश्ता लेकर पहुंचा, मां-बाप बोले- हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, सरदार बोला- कोई बात नहीं जी, हम एक-दो घंटे बाद आ जायेंगे।

लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे? लड़का- शाहजहांन जैसा, लड़की- तो ताजमहल बनवाओ, लड़का- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं।

पप्पू- मेरे बाप के आगे बड़े - बड़े लोग कटोरी लेके खड़े होते हैं, लड़की- अच्छा! कौन है तुम्हारा बाप? पप्पू- पानी पूरीवाला।

पप्पु बहूत देर से एक लड़की को घुर रहा था, लड़की- तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या? पप्पु- है न तभी तो देख रहा हूं, क्योंकि मां को बहू और बहन को भाभी चाहिए।

जरुरत से ज्यादा भगवान को याद मत किया करो क्योंकि, किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो, लेने के देने पड़ जायेंगे।

पत्रकार- 80 साल की उम्र में भी आप बीवी को डार्लिंग कहते हैं, इस प्यार का राज क्या है? बूढ़ा व्यक्ति- बेटे 20 साल पहले इनका नाम भूल गया था, पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए डार्लिंग कहता हूं...

कहानी — भाव से बढ़कर कोई पूजा नहीं

एक करोड़पति को करोड़ों का घाटा लगा था, और नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, फुर्सत ही नहीं मिली थी। कई मंदिर भी बनवाये थे, लेकिन आज इस दु:ख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया, ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, बोहनी की आदत जो होती है, कमबख्त यहां भी नहीं छूटी। लेकिन यह देख कर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले से ही मन्दिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे खड़ा हो गया, कि भिखारी क्या मांग रहा है? धनी आदमी सोचता है, कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं? और भिखारी सोचता है, कि मुसीबतें मेरे पास हैं। धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी? एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी न थी! उसने सुना, कि भिखारी कह रहा है - हे परमात्मा ! अगर पांच रुपए आज न मिलें तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आत्महत्या कर लूंगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए पांच रुपए होना बिलकुल आवश्यक हैं ! मेरा जीवन संकट में है ! अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है - कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। तो उसने झल्लाकर अपने जेब से पांच रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिए और कहा - जा ये ले जा पांच रुपए, तू ले और जा जल्दी यहां से। अब वह परमात्मा से मुखतिब हुआ और बोला - प्रभु, अब आप ध्यान मेरी तरफ दें, इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे पांच करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्करा उठे, बोले - एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा, तुम सब लोग यहां कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है? धनी आश्चर्यचकित हुआ, बोला - प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले - प्रेम ! मैं भाव का भूखा हूं। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

नौकरी में कार्यभार रहेगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। आय में निश्चितता रहेगी। जोखिम न लें। एकाएक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लापरवाही न करें।

वृषभ

व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। लाभ देगा। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी। प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

मिथुन

दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए काम करने का मन बनेगा। फिजूलखर्ची ज्यादा होगी। शत्रु भय रहेगा। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी।

कर्क

व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं। कोई बड़ी समस्या का अंत हो सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

सिंह

स्वयं के काम पर ध्यान दें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। विवाद को बढ़ावा न दें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा। कार्यकुशलता कम होगी।

कन्या

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। भाग्य का साथ मिलेगा।

तुला

सुख के साधन जुटेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

वृश्चिक

तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। किसी जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

धनु

भागदौड़ होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। लाभ के लिए प्रयास करें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवाद से क्लेश हो सकता है।

मकर

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि अपमान हो। व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा।

कुम्भ

भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी। आशंका व कुशंका रहेगी।

मीन

यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

रणवीर की 'रामायण' ने की थियेट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की डिमांड

रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल की फिल्म रामायण : पार्ट 1 को रिलीज होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन ये फिल्म अभी से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इसे भारत की सबसे महंगी फिल्म के तौर पर मेकर्स ने प्रोजेक्ट किया है और इसलिए फिल्म का स्केल भी बहुत बड़ा है। फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा, लेकिन अभी इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। देश के कई बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस रामायण के राइट्स को खरीदने की फिराक में हैं।

रामायण जैसी फिल्म, जिसे देश की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है, उसके थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की कीमत ने भी डिस्ट्रिब्यूटर्स के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में आई वैरायटी इंडिया ने सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस, अनिल थडानी की एए फिल्म्स और पैन स्टूडियोज से प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रामायण के पैन इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर खुलकर बात की। हालांकि चर्चा अभी शुरुआती स्टेज पर है। आने वाले महीने में डील फाइनल होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले उसकी कीमत एक बड़ा मसला बन गई है।

रामायण के हिंदी थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की कीमत प्रोड्यूसर ने 450 करोड़ रुपये तय की है। इस कीमत ने इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं। इससे पहले भारतीय सिनेमा के इतिहास में कोई भी फिल्म इस कीमत के आस-पास भी नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कीमत सुनकर अनिल थडानी, जयंतीलाल गड़ा और अन्य डिस्ट्रिब्यूटर्स हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने नमित मल्होत्रा से अपनी डिमांड कम करने की गुजारिश की है। बताया गया है कि नमित मल्होत्रा ने जो कीमत तय की है और डिमांड रखी है, वो उस पर अडिग हैं। उनका मानना है कि कीमत फिल्म के स्केल, मार्केट संभावनाओं और अभी से ही बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की उम्मीद को देखते हुए रखी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले दौर की बातचीत अब तब शुरू होगी, जब मेकर्स फिल्म का अगला प्रमोशनल एसेट जारी करेंगे।

कोर्ट के फैसले के बाद फिर लौटेगा रणवीर की 'धुरंधर' का तूफान

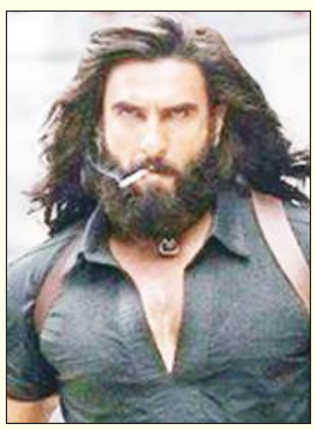

आदित्य धर की स्पाई फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बाकी सारी फिल्मों को पीछे छोड़कर करोड़ों का बिजनेस कर लिया है। वहीं कुछ समय से ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है। लेकिन ओटीटी पर इस फिल्म के कुछ सीन्स को कट कर के रिलीज किया गया था, जिससे फैंस काफी नाराज थे और मेकर्स से पूरी फिल्म री-रिलीज करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के दूसरे पार्ट में सेना की गोपनीय जानकारियां दिखाने के आरोपों पर केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से जांच करने को कहा है।

इसी बीच मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। मेकर्स ने धुरंधर 2 की स्ट्रीमिंग डेट तय कर, फिल्म के दूसरे पार्ट धुरंधर : द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। इस पार्ट का प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे होगा। इसके बाद, 5 जून से दर्शक इसे सिर्फ जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे। फिल्म के दोनों ही पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं और दोनों फिल्मों की कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है।

'धुरंधर 2' पर इस समय कानूनी विवाद चल रहा है। फिल्म का नया वर्जन आना, जब इसके दूसरे पार्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी विवाद चल रहा है। एसएसबी के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी गुप्त जानकारियां दिखाई गई हैं, जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को दिए निर्देश इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी की ओर से उठाए गए मुद्दों को छोड़ नहीं सकते।

कांस्टेबल दीपक कुमार द्वारा दायर की गई इस याचिका में लगाए गए आरोपों को कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से जांच करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या फिल्म से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है या नहीं, दोनों पार्ट ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ रुपए की कमाई है।

बॉलीवुड | मन की बात

आलोचना करने वालों को खुद रियलटी शो का हिस्सा बनना चाहिए : गीता कपूर

फेमस रियलिटी शोज में दिखाई जाने वाली कंटेस्टेंट्स की भावुक कहानियों को लेकर दर्शक जानते हैं कि ये सिर्फ टीआरपी बटोरने का एक जरिया हैं। अक्सर लोग इन शोज और जजों के फैसलों को पूरी तरह स्क्रिप्टेड और नकली बताते हैं। अब इस पूरे विवाद, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और गलतफहमियों पर मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। कोरियोग्राफर गीता कपूर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि असलियत जानने के लिए लोगों को खुद रियलिटी शोज का हिस्सा बनकर देखना चाहिए, ताकि वे इसके पीछे की असली दुनिया और सच को समझ सकें। हाल ही में एक इंटरव्यू में गीता कपूर ने रियलिटी शोज को लेकर लोगों के नजरिए और उसकी ऑथेंटिसिटी पर उठने वाले सवालों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जो लोग इन शोज की आलोचना करते हैं, उन्हें खुद आकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आज खुद सोचिए, आप बाहर जाकर लोगों को कितना समझ सकते हैं? भला कोई डांस को कैसे स्क्रिप्ट कर सकता है? डांस को कोरियोग्राफ किया जा सकता है, उसे बेहतर ढंग से पेश किया जा सकता है, किसी की पर्सनैलिटी को संवारा जा सकता है। गीता कपूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हां, आप बैठकर यह जरूर प्लान कर सकते हैं कि किसी के टैलेंट को सबसे बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने कैसे पेश किया जाए. अगर लोग इसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं, तो यह सिर्फ टैलेंट को दिखाने का एक सुनियोजित तरीका है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि यह स्क्रिप्टेड है, तो क्या उनका मतलब यह होता है कि जज भी लिखी-लिखाई लाइनें बोलते हैं? जहां तक मेरी बात है, अगर मुझे कोई ऐसी लाइन लिखकर दी जाए, जिसमें यह तय हो कि मुझे किसी के बारे में क्या बोलना है, तो मैं उसे हाथ तक न लगाऊं।

भारत का इकलौता गांव जहां हर घर में घूमते हैं सांप, एक ही छत के नीचे रहते इंसान और नागराज

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है, जिसे शेतफल के नाम से जाना जाता है। आज के समय में यह पूरे भारत में स्नेक विलेज के रूप में मशहूर हो चुका है। शेतफल की सबसे खास बात यह है कि यहां इंसान और खतरनाक सांपों (खासकर कोबरा) के बीच एक अद्भुत सह-अस्तित्व देखने को मिलता है। गांव के लोग पारंपरिक रूप से इन जहरीले सांपों को डर या खौफ की नजर से नहीं, बल्कि गहरी आस्था और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। शेतफल गांव को जो बात दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बनाती है, वह है यहां के घरों की बनावट। गांव के लगभग हर घर के अंदर सांपों के रहने और आराम करने के लिए एक विशेष स्थान बनाया जाता है। इसे सांपों का विश्राम स्थल माना जाता है। गांव वालों का मानना है कि घर की सीमा के भीतर सांपों के लिए एक उचित जगह होनी चाहिए। यह सदियों पुरानी परंपरा है जिसे आज भी हर घर में पूरी आस्था के साथ निभाया जा रहा है। पर्यटकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे वन्यजीवों को परेशान न करें और बिना अनुमति किसी के निजी घर में प्रवेश न करें। हमेशा गांव से जुड़ी स्थानीय रीति-रिवाजों और आस्थाओं का सम्मान करें। अगर आप भी इस अद्भुत स्नेक विलेज की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक रहता है, जबकि गर्मियों में यह इलाका काफी गर्म हो सकता है। इस गांव की यह अनोखी पहचान मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और सांपों की पूजा करने की प्राचीन परंपरा में गहराई से निहित है। हिंदू संस्कृति और मान्यताओं में नाग पूजा को हमेशा से सांस्कृतिक सम्मान के साथ जोड़ा गया है। शेतफल के निवासियों का अटूट विश्वास है कि सांप बेहद पवित्र होते हैं। भले ही वे कितने भी जहरीले क्यों न हों, ग्रामीण उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि सांप उनके घरों के भीतर एक सम्मानित सदस्य की तरह विचरण करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन खतरनाक सांपों ने आज तक गांव के किसी भी निवासी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। गांव वालों का दृढ़ विश्वास है कि यह शांतिपूर्ण और आपसी सह-अस्तित्व का ही नतीजा है कि सांप उनके लिए खतरा नहीं बनते।

अजब-गजब | यह है देश का अनोखा स्टेशन

यहां न टिकट खिड़की, न प्लेटफॉर्म, बैग लेकर टिकट बांटता है ठेकेदार, वजह है अजीबो गरीब

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसका कुल रूट लगभग 68,000 से 70,000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन, आधुनिक सुविधाएं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और हाईटेक प्लेटफॉर्म आज भारतीय रेलवे की पहचान बन चुके हैं। लेकिन इसी देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जिसके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह स्टेशन सालों तक बिना प्लेटफॉर्म और बिना टिकट खिड़की के चलता रहा। यहां टिकट लेने के लिए यात्रियों को किसी काउंटर पर लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, बल्कि यहां एक ठेकेदार बैग में टिकट लेकर स्टेशन पहुंचता था और वहीं टिकट बेचता था। यही अनोखी व्यवस्था अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

दरअसल, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब लीलमा और जैसिंधर रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। ये स्टेशन काफी पुराने बताए जाते हैं और इनका इतिहास आजादी से पहले का माना जाता है। सीमा से सटे इलाके में होने की वजह से यहां लोगों की जनसंख्या कापी कम है और लंबे समय तक रेलवे सुविधाओं का विकास भी बहुत धीमी गति से हुआ। यही कारण रहा कि इतने सालों तक यहां यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाईं। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सबसे जरूरी सुविधा माना जाता है, लेकिन लीलमा और जैसिंधर स्टेशन पर लंबे समय तक प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं था। ट्रेनें सीधे पटरियों के किनारे रुकती थीं और यात्रियों को नीचे से ही ट्रेन में चढ़ना पड़ता था। यह काम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल भरा होता था। कई बार यात्रियों को भारी सामान के साथ ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने में परेशानी होती थी और छोटी सी लापरवाही हादसे का कारण बन जाती थी।

इस स्टेशन की सबसे अनोखी बात इसकी टिकट व्यवस्था थी। यहां कोई टिकट खिड़की या बुकिंग ऑफिस नहीं था. ट्रेन आने से करीब 10 से 15 मिनट पहले एक ठेकेदार बैग में टिकट लेकर स्टेशन पहुंचता था। यात्री उसी से टिकट खरीदते थे। यह तरीका आज के डिजिटल दौर में बेहद अलग और हैरान करने वाला लगता है। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इस व्यवस्था के बारे में जब लोगों तक बात गई तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए कि भारत में ऐसा स्टेशन हो भी सकता है।

हालांकि अब रेलवे प्रशासन ने इन स्टेशनों की स्थिति सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इन स्टेशनों पर करीब 600-600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य जरूरी काम भी शुरू किए गए हैं। उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा इन स्टेशनों पर बिजली और जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रेलवे का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर यात्रा सुविधाएं देना है।

तमिलनाडु में झुके नारियल को लेकर चढ़ा सियासी पारा

» टीवीके सरकार में शामिल होने पर रार

वीसीके व डीएमके में छिड़ी जुबानी जंग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और उसके पूर्व सहयोगी वीसीके के बीच तब तीखा टकराव शुरू हो गया। अब वहा जुबानी जंग में नारियल की एंट्री हो गई है। दरअसल पूरी बयानबाजी तब शुरू हुई जब वीसीके, टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई। डीएमके नेता ए राजा के झुके हुए नारियल के पेड़ वाले कटाक्ष पर वीसीके ने पलटवार करते हुए डीएमके को उसके पुराने गठबंधनों, विशेषकर भाजपा के साथ सहयोग, की याद दिलाई।

विदुथलाई चिरुथाइगल काची और आईयूएमएल के टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बाद डीएमके और उसके पूर्व सहयोगी वीसीके के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस फैसले से वफादारी और गठबंधन की राजनीति को लेकर तीखी आलोचना और राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। यह जुबानी जंग तब शुरू हुई जब वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), जो 26 के विधानसभा चुनाव तक डीएमके के सहयोगी थे, ने टीवीके सरकार को समर्थन दिया। विधानसभा में टीवीके को साधारण बहुमत के 118 अंक नहीं मिले।

राजा ने झुकते नारियल के पेड़ से की वीसीके की तुलना

एक्स पर एक पोस्ट में राजा ने इशारों-इशारों में कहा कि अगर मेरे बगीचे का नारियल का पेड़ झुककर पड़ोसी को कच्चा नारियल दे, तो साहित्य में उसे मुत्तथेंगु (आंगन का पेड़) कहा जाएगा। राजनीति में हम इसे क्या नाम दें? उन्होंने पोस्ट का अंत तमिल जिंदाबाद कहकर किया। वीसीके और आईयूएमएल ने पहले स्पष्ट किया था कि टीवीके सरकार को उनका समर्थन तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन को रोकने के उद्देश्य से था, और उन्होंने यह भी कहा था कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को उनके स्वतंत्र निर्णय की जानकारी दे दी गई थी। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन दिया।

कांग्रेस को हराने के लिए संघ परिवार के साथ गठबंधन किया : वीसीके

राजा की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए वीसीके ने कहा कि वह अन्य पार्टियों की दया पर नहीं पनपी और जोर देकर कहा कि उसका राजनीतिक आधार शोषित समुदायों के पसीने और खून से बना है। वीसीके ने एक्स पर कहा कि दल-बदल के बारे में बात करने का अन्य दलों को क्या अधिकार है? किसका इतिहास है कि उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए संघ परिवार (भाजपा) के साथ गठबंधन किया? किसका स्वार्थ है कि वे वाजपेयी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और फिर उसी भाजपा का विरोध किया? तमिलनाडु ने ऐसे कई राजनीतिक नाटक देखे हैं।

किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है भाजपा : सिसोदिया

» आप नेता ने सुवेंदु के निजी सहायक की हत्या के मामले में दूसरे को पकड़ने पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई को लेकर आप के नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मामले में गिरफ्तारियों के संचालन पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने लिखा कि सिंह और उनका परिवार भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ों, ईडी-सीबीआई की छापेमारी और फर्जी मामलों में गिरफ्तारियों का भी जमकर समर्थन किया होगा।

उन्होंने इन सब पर भी तालियां बजाई होंगी। भाजपा को उनकी तालियों से और भी ज्यादा हिम्मत मिली होगी – कि जब चाहे, जिस आरोप में चाहे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, मुठभेड़ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज सिंह को रिहा नहीं किया जाता तो अंधभक्त मीडिया पुलिस द्वारा आरोपी को गोली मारने की घटनाओं को प्रचारित कर देता। लेकिन शुक्र है भगवान का। वे बच गए। वरना, भाजपा के अंधभक्त मीडिया पूरे देश में शोर मचा रहा होता कि भाजपा की पुलिस ने मास्टरमाइंड को मार गिराया है। भाजपा के लिए जो वाहवाही वे दे रहे थे, वही उनके अपने ही मुठभेड़ में गोलियों में तब्दील होने वाली थी। हत्या मामले में गिरफ्तार राज सिंह के इस आरोप के बाद ये बयान सामने आया है कि पुलिस ने गलत पहचान के आधार पर उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया था और बाद में सीबीआई की जांच के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

पंजाब का करो या मरो का मुकाबला लखनऊ से आज

» प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखने के लिए चाहिए सिर्फ जीत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आईपीएल के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी। पंजाब के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि उसकी नजरें प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने पर होंगी। वहीं, एलएसजी घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेगी। हालांकि, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम अपने खराब प्रदर्शन की वजह से पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स पर मिली जीत ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। पंजाब ने 13 मैचों में छह मुकाबले जीते हैं और अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। ऐसे में एलएसजी के खिलाफ जीत से उसके 15 अंक हो जाएगा।

हालांकि यह मैच जीतने के बाद भी पंजाब को राजस्थान रॉयल्स की जीत-हार पर निर्भर रहना होगा, जो इतने ही मैचों में 14 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। यदि राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला जीतती है तो 16 अंकों के साथ उसे प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। लगातार छह हार ने पंजाब किंग्स की इस प्लेऑफ की राह मुश्किल बना दी है। सीजन की शुरुआत में शानदार लय में दिख रही टीम अब दबाव में नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने शुरुआती मुकाबलों में आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए खुद को खिताब के दावेदारों में शामिल कर लिया था, लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे चरण में टीम का प्रदर्शन पूरी तरह बिखर गया। पंजाब किंग्स ने अपने पहले दस मुकाबलों में छह जीत दर्ज कर अंक तालिका में मजबूत स्थिति बना ली थी। लेकिन इसके बाद टीम लगातार हार के भंवर में फंस गई। टीम की सबसे बड़ी समस्या प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही। शुरुआती मैचों में जहां शीर्ष क्रम ने जिम्मेदारी निभाई, वहीं पिछले मुकाबलों में बल्लेबाज बड़े मौकों पर विफल रहे। गेंदबाजी विभाग में भी पंजाब को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा। आखिरी ओवरों में रन रोकने में टीम असफल रही, जबकि स्पिन आक्रमण अपेक्षित असर नहीं छोड़ सका।

हार कर भी जीती आरसीबी, क्वालिफायर-1 में पहुंची

हैदराबाद। उप्पल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को 55 रनों से हरा दिया। हालांकि, इस जीत के बावजूद टीम शीर्ष-दो में एंट्री करने में नाकाम रही और अब वह एलिमिनेटर मैच खेलेगी। वहीं, आरसीबी हार के बावजूद शीर्ष पर बरकरार रही और अब उसका सामना गुजरात टाइटंस से क्वालिफायर-1 से होगा। हैदराबाद के दिए 256 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी आरसीबी 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन बना सकी और 55 रन से मैच हार गई। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए थे। एसआरएच-आरसीबी दोनों का यह आखिरी लीग मैच था। दोनों टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं। आरसीबी 14 मैचों से 18 अंक लेकर बेहतर रन रेट के आधार पर पहले, गुजरात टाइटंस 14 मैचों से 18 अंक लेकर दूसरे और एसआरएच 14 मैचों से 18 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है।

आहत महिला निरीक्षक का छलका दर्द !

» बोली- वार्ड नहीं, प्रताड़ना मिली

» जोन-3 के जोनल अधिकारी पर भेदभाव और वित्तीय अनियमितता के लगाए गंभीर आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। नगर निगम जोन-3 में तैनात महिला समेत कई कर्मियों ने जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। कर्मियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ लगातार पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि सात माह पूर्व जोन-3 में तैनाती के बाद उन्हें कुल 19 वार्डों में से केवल 3 वार्ड ही आवंटित किए गए,जबकि अन्य निरीक्षकों को अधिक क्षेत्र दिए गए।

इसके बावजूद उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन मॉनिटरिंग और वीवीआईपी कार्यक्रमों में पूरी जिम्मेदारी से कार्य किया। महिला कर्मी का आरोप है कि मेडिकल अवकाश से लौटने के बाद उनके वार्ड वापस ले लिए गए और 18 कार्यदिवस बीत जाने के बावजूद उन्हें दोबारा कोई वार्ड आवंटित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगवाए गए और उच्चाधिकारियों से फील्ड में अनुपस्थित रहने की नोटिस तक दिलवाई गई। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जोनल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत और स्त्रीसूचक कटाक्ष किए जाते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। महिला कर्मी ने आरोप लगाया कि अधिकारी सीधे संवाद करने के बजाय वाहन चालक अनुज यादव के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं और फोन तक नहीं उठाते। मामले को और गंभीर बनाते हुए पत्र में करोड़ों रुपये के सफाई कार्यों से जुड़े बिलों में वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है।

नगर आयुक्त से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

महिला कर्मी ने नगर आयुक्त से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, विशाखा समिति गठित कर व्यवहार की जांच हो तथा जांच पूरी होने तक उनका स्थानांतरण किसी अन्य जोन में किया जाए ताकि वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। नगर निगम के अंदर यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

नीट परीक्षार्थियों के लिए बिहार में मुफ्त बस सेवा : सम्राट चौधरी

» सीएम ने मठ-मंदिरों से की खास अपील

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। नीट पेपर लीक मामले के बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने की संभावनाओं के बीच बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क होगी।

उन्होंने जिला प्रशासन, राज्य के मठ-मंदिरों तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से भी एक खास अपील की है। कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग करें।

हरियाणा सरकार बिना बिजली खरीदे ही लुटा रही करोड़ों: हुड्डा

» बोले कांग्रेस नेता- भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से जूझ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर कहा कि भीषण गर्मी के बीच पूरा प्रदेश बिजली संकट का सामना कर रहा है जबकि सरकार बिना बिजली खरीदे ही करोड़ों रुपये लुटा रही है। हुड्डा ने कहा कि राज्य के 17 जिलों से मिल रही रिपोर्ट के अनुसार शहरों और गांवों में रोजाना 3 से 14 घंटे तक अघोषित बिजली कट लग रहे हैं। कई जगह ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर जल रहे हैं। बिजली की केबल में आग और फ्यूज उड़ने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

जगमग योजना के बावजूद गांवों में केवल 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है जिससे पेयजल और सिंचाई की समस्या भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हरियाणा को पावर सरप्लस राज्य बनाया गया था। जबकि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा सकी है। हुड्डा ने सिक्किम की तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड को लेकर भी सवाल उठाते कहा कि सरकार ने 200 मेगावाट बिजली समझौते के तहत बिना एक भी यूनिट बिजली लिए 1345 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।

4PM बंद कराने का दांव सरकार को पड़ा उल्टा

एंकर फिज़ा के इंस्टा पर फॉलोवर्स की बौछार

मैं जब भी बिखरा हूँ ,दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ..

» युवा पत्रकार ने दिखा दिया- युवा जोश तानाशाही सत्ता के भी उड़ा सकता है होश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। तुम लाख कोशिश कर लो ,मुझे तोड़ने की ,मैं जब भी बिखरा हूँ ,दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ... ये शेर मौजू है देश के सबसे लोकप्रिय यू-ट्यूब चैनल 4 पीएम के लिए। दरअसल तेजतर्रार एंकर फिजा ने अपनी रील में सरकार से सवाल पूछा कि 4 एम क्यों बंद कराया गया? लेकिन ये सवाल शायद सत्ता को नागवार गुजरा और मोदी सरकार ने डर के मारे उसकी रील ही बंद कर दी।

ऐसा करके सरकार ने सोचा कि वह उसे झुका देंगे मगर सत्ता की हनक व हेकड़ी तब निकल गई जब वो रील सिर्फ़ एक घंटे में तीस लाख से ज़्यादा लोगों की नजर में आ गई। इसी के साथ जता दिया कि सच को दबाना इतना आसान नहीं है। रील से सरकार इतना बौखाला गई उसने तुगलकी फरमान दे डाला-ये रील प्रतिबंधित की जाती है।

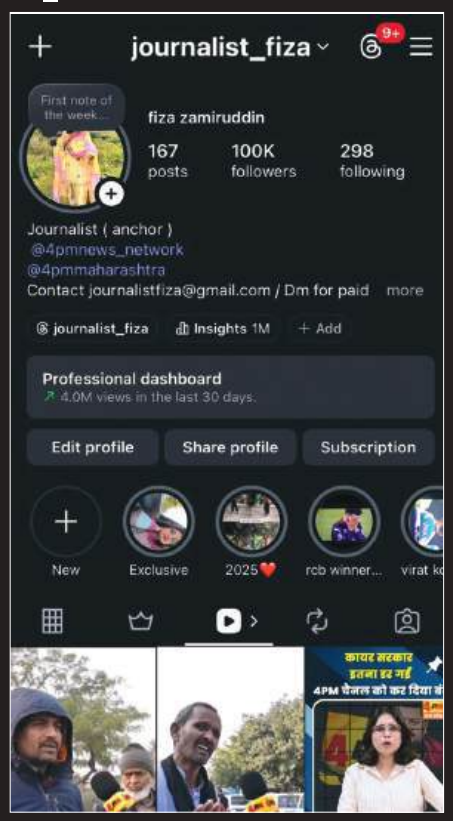

तीन हजार फॉलोवर्स लाखों में पहुंचे

लेकिन उस आदेश का बिल्कुल उल्ट हो गया उधर जैसे ही रील पर रोक लगी फिज़ा के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बिजली की रफ़्तार से बढ़ने लगे। जो लड़की कल तक 3 हजार फॉलोवर्स पर थी। आज वो एक लाख पार कर चुकी है। वो भी सिर्फ़ एक महीने में।

दरअसल सरकार से सवाल पूछने के बाद उसने डरने से इंकार कर दिया था उसने फिर वही सवाल सरकार की आंखों में आखें डाल कर पूछी। अहंकारी सत्ताधीशों को यही अखर गया। उसके रील को बंद कर दिया गया। उसने सिर्फ़ एक सवाल पूछा था – 4पीएम से इतना डर क्यों लगता है सरकार को? बस इतना कहने के लिए उसने रील बनाई थी। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने देख ली। फिर दो घंटे बाद उस रील पर भी रोक लगा दी गई।

उसका निडर होना ही सरकार को अखर गया

26 का भारत है जितना दबाओगे उतना विस्फोट होगा

वर्तमान में अब हाल ऐसा हो गया कि सत्ता सिर्फ़ चैनलों से नहीं डर रही। अब वो एक लड़की के मोबाइल कैमरे से भी डरने लगी है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये 26 का भारत है यहाँ जितना दबाओगे, उतना विस्फोट होगा।

बांद्रा में जब बुलडोज़र चलाने पर सरकार से पूछा सवाल

फिजा ने मुंबई में भी बेहतरीन रिपोर्टिंग की। जब बांद्रा में बुलडोज़र चला, मस्जिदें तोड़ी गईं। लोग डरे हुए थे। तब फिजा कैमरा लेकर सड़क पर पहुंची। पुलिस के सामने तन कर खड़ी हुई। बेबाक सवाल पूछे। वो वीडियो महाराष्ट्र में आग की तरह फैल गया। उसकी वीडियो ने मौजूदा सरकार की चूले हिला दीं।

बढ़ते फालोवर्स सरकार को डरा रहे

फिजा की बहादुरी को लोग पसंद कर रहे हैं उसे सुन रहे हैं क्योंकि जनता अब स्क्रिप्टेड एंकर नहीं देखना चाहती। जनता अब वो लड़की देख रही है जो सड़क पर खड़े होकर सत्ता से सवाल पूछ रही है। ये सिर्फ़ एक लाख फॉलोवर नहीं हैं। ये सरकार के डर का मीटर है। हर नया फॉलोवर सत्ता को एक संदेश दे रहा है –अब डर तुम्हें लग रहा है। इतिहास गवाह है जब-जब सत्ता ने आवाज़ दबाने की कोशिश की है तब-तब नई आवाज़ें पैदा हुई हैं।4 पीएम को बंद किया, तो हजारों नए 4पीएम पैदा हो गए। किसी ने सही कहा है तानाशाही की सबसे बड़ी हार तब शुरू होती है, जब नौजवान डरना बंद कर देते हैं।

सरकार से डरने वाले लोग नहीं : इकरा हसन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सपा सांसद सहारनपुर के गंगोह में स्थित ईस्सोपुर गांव पहुंची थी, जहां उन्होंने आदित्य के परिजनों से मुलाक़ात की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया, सपा सांसद ने कहा कि यूपी में फरियादी पर ही एफआईआर कह दी जाती है।

सपा सांसद इकरा हसन ने यूपी की क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है लेकिन, मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में एक तीसरी-चौथी घटना हो गई है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी हैं, उसमें न तो कोई गिरफ़्तारी हो रही है और ना ही संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है।

हमारा पर्सनल अकाउंट हैक कर धमकियां दी जा रही : दिपके

» कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शनिवार को दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट और पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया है। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब उनका व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है और उसे लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा था, अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट प्रभावित हुए हैं।

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी पर कार्रवाई की जा रही है. इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है, मेरा निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया है, ट्विटर अकाउंट रोक दिया गया है और बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया है. फिलहाल हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म तक हमारी पहुंच नहीं है. इसके बाद किए गए किसी भी पोस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न माना जाए। अभिजीत दिपके बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं. उन्होंने करीब एक सप्ताह पहले इस व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद यह प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 1.9 करोड़ फॉलोअर्स हो गए थे।

'कॉकरोच जनता पार्टी' ट्रेंड उस विवाद के बाद शुरू हुआ जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित टिप्पणी को लेकर चर्चा हुई थी। बताया गया कि वरिष्ठ वकील का दर्जा देने से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

स्ट्रीट डॉग को संरक्षण देने वालों को धमकी

» कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर तीखी बहस

» पीड़िता ने सीएम जनसुनवाई पोर्टल में की शिकायत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रीट डॉग को संरक्षण देने के लिए सरकारों को फटकार लगा रही है तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बेजुबानों को सहारा दे रहे हैं लोगों को पेरशान कर रहे हैं। इसी तरह का मामला राजधानी लखनऊ में देखने को मिला जहां एक आवसीय एरिया में कुत्तों का खाना खिलाने को लेकर बात इतनी बढ़ी की जान से मारने-पीटने की धमकी तक दी जाने लगी। मामला इतना तूल पकड़ गया कि सीएम के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत तक पहुंच गई।

दोनों की झड़प का वीडियो भी वायरल हो गया। इसमें पीड़िता व उनके पति कुत्तों को खाना खिला रहे है जबकि दूसरा पक्ष उन्हें रोक रहा है। उन्हें आगे ऐसा करने पर उनको मारने की धमकी दे रहा है। मामला ओमेक्स आर लखनऊ का है। पीड़िता ऋतु झा ने मयंक राज के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता के अनुसार 22 मई 26 को रात लगभग 10 बजे, मेरे पति प्रभात झा और मैं टावर 22, ओमेक्स आर(2, लखनऊ के तहखाने में मौजूद थे, जब मयंक राज ने मेरे पति पर शारीरिक हमला किया।

Jansunwai
Integrated Grievance Redressal System, Uttar Pradesh
Reference Number :- 40015720061295
Beneficiary Details
Application Details
Beneficiary / Complaint Area Details

घटना के दौरान, उन्होंने मैं तुम्हें जान से मार दूंगा कहकर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद से, डराने-धमकाने का सिलसिला जारी है और बढ़ता जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि भीड़ बनाकर हमारे घर लाया जाएगा और हमें डराया-धमकाया जाएगा और नुकसान पहुंचाया जाएगा। मेरे पति और मैं अपनी जान और सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से भयभीत हैं और हमें अपने घर में और हिंसा होने की आशंका है। शिकायत में दर्ज किए गए कृत्य संज्ञेय अपराधों को दर्शाते हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, 23 की धारा 115, 3512, 3513, 352, 189, 190 और 35 के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही कानून के अन्य लागू प्रावधान भी।

सुरक्षा की मांग की

पीड़िता ने कहा मैं आपसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि संबंधित पुलिस अधिकारियों, जिनमें थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ भी शामिल है, को मयंक राज और इसमें शामिल अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच करने और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। मैं आगे अनुरोध करती हूं कि किसी भी भीड़, समूह या व्यक्ति से तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए जो हमें धमकाने, डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे निवास पर आने का प्रयास कर रहा हो।

चीन की कोयला खदान में विस्फोट, 90 लोगों की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। शुक्रवार देर रात चीन त्तरी चीन के शांक्सी प्रांत स्थित लियुशेनयु कोयला खदान में भयानक गैस विस्फोट हुआ। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग ने बचाव कार्य में पूरी ताकत झोंकने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।

चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ के अनुसार, यह गैस धमाका शुक्रवार देर रात किनयुआन काउंटी की लियुशेन्यु कोयला खदान में हुआ। हादसे के वक्त खदान के भीतर 247 मजदूर काम कर रहे थे।चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अधिकारियों से घायलों के इलाज और खोज व बचाव अभियान चलाने में कोई कसर न छोड़ने का आह्वान किया है। साथ ही, उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने और कानून के अनुसार कड़ी जवाबदेही तय करने का भी आदेश दिया।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा